परिसर तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कोई भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों से मुक्त नहीं है। जिन 25 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के 275 जिलों का सर्वेक्षण किया गया उनमें से 235 जिले इन्डेमिक (स्थानिकमारी से ग्रस्त) हैं, जहां यह 10% से अधिक फैली हुई है। देश तथा साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ इन्टरनेशल काउंसिल फार कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसआर्डर्स के विशेषज्ञों ने आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों को रोकने, नियंत्रित करने तथा समाप्त करने के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली तथा सस्ते तरीके के रूप में आयोडीनयुक्त नमक के उपयोग की सिफारिश की है। भारत सरकार ने सार्वजनिक हित में नेशनल आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसआर्डस कंट्रोल प्रोगाम, जिसके अंतर्गत आयोडीनयुक्त नमक को आपति करना कार्यक्रम की मुख्य कार्य नीतियों में से एक है, को सारे देश में लागू करने का निर्णय किया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गैर आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर पूरी रोक है, जबकि 2 राज्यों में इस पर आंशिक रूप से रोक है। केरल राज्य में इस पर कोई रोक नहीं है।

देश के विभिन्न भागों में घेघा तथा आयोडीन की कमी से होने वाली अन्य खराबियों पर आयोडीनयुक्त नमक के प्रभाव के बारे में समय-समय पर किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि पौषणिक आयोडीन की कमी से होने वाली खराबियों में उल्लेखनीय कमी आई है।

दालों के निर्यात पर रोक लगाया जाना

1440. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री कपिल सिब्बल:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में दालों की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अक्तूबर, 1998 के अंत में सरकार द्वारा संबंधित विभाग को दालों के निर्यात पर रोक लगाने संबंधी सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या दालों के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो यह प्रतिबंध किस तारीख से लागू किया गया था?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) से (ग) दालों सहित खाद्यान्नों की निर्यात-आयात नीति संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करते हुए भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा तय की जाती है। वर्तमान निर्यात-आयात के अनुसार दालों का 5 किलोग्राम तक के उपभोक्ता पैक में मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है। दालों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

Time-Limit for Adjudication of Complaints under Consumer Protection Act

1441. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the consumer protection Act, 1986 stipulates a time limit of 90 days for adjudication of complaints;

(b) if so, the details thereof;

(c) the percentage of cases filed before the district forums and state commissions which are disposed off within the stipulated time limit;

(d) whether the recommendations of the working group constituted in 1994 have been implemented; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) According to the provisions of the Consumer protection Act, 1986 and the Rules framed thereunder the State Commission and the district for a set up under the Act are required to dispose of complaints, as far as possible, within 90 days from the date of receipt of the Notice by the opposite party and within 150 days if it requires analysis or testing of the commodity in question. The National Commission is required to dispose of appeals, as far as possible, within 90 days from date of first hearing.

(c) As per the information made available by the States/UTs., 31% and 25% cases were disposed of within 90 days and

21% and 24% cases were disposed of between 90-150 days by the district for a and State Commissions respectively.

(d) and (e) No. Sir. The proposals for the Amendment of the Consumer protection Act, 1986 as recommended by the Working Group constituted in 1994 and subsequently by an Expert Group in 1997 are under consideration of the Government.

Government Directive to Purchase Paddy and Wheat from Farmers

1442. SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating to direct the Food Corporation of India to purchase paddy and wheat direct from the farmers; and

(b) if not, why such a proposal cannot be considered to break the monopoly of the Millers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) and (b) Food Corporation of India procure paddy and wheat for Central Pool directly from the farmers in the allotted mandis/purchase centres in the concerned States/UTs except in Punjab and Haryana where FCI State procuring agencies purchase foodgrains through Katcha Arhtias (licensed Commission Agents) as per the Punjab Haryana Agricultural produce Marketing Act. The Katcha Arhtias provide necessary services to the farmers and buyers. Stocks are sold through auction, and FCI/State agencies make the purchases at the declared procurement price by participating in the bidding.

The farmers are free to sell their produce to FCI/State agencies at the MSP/ procurement price or to private traders/ millers as is advantageous to them.

Non-Availability of Packing Material for Apples

1443. SHRIMATI JAYAPARDA NAHATA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether non-availability of packing material is leading to rotting of fruit (Apple) worth crores of rupees in Kashmir and in other Apple Producing areas; and

(b) if so, the steps taken by Government to save fruit growers from huge losses?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI SATYAPAL SINGH YADAV): (a) The Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) has informed that it has not received any report from the State Governments regarding rotting of fruits like apples due to non-availability of packing material.

(b) Does not arise in view of the reply to part (a) above. However, the National Horticulture Board implements a scheme entitled Integrated Project on Management of Post-Harvest Infrastructure of Horticultural Crops under which assistance is provided in the form of subsidy on merit for improved packaging to minimise post-harvest losses.

तलहन पेराई उद्योग

1444.**श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में तिलहन पेराई उद्योग विश्व का सबसे बड़ा पेराई उद्योग है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और मार्च, 1998 के अंत में तिलहन पेराई की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुल अधिष्ठापित क्षमता का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है;